

प्रेषक,

जे० पी० जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-1

देहरादून दिनांक: 18 जनवरी, 2011

विषय: पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल में 11 के० वी० विद्युत सबस्टेशन की स्थापना तथा 11 के० वी० लाईन के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पुनर्विनियोजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्राविजनिंग एण्ड मॉडर्नाइजेशन, पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-डी० जी०-दो-526(2)/2002, दिनांक: 25 फरवरी, 2010 तथा पत्र संख्या-डी० जी०-दो-525(2)/2002, दिनांक 08 नवंबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल में स्थायी विद्युत संयोजन हेतु 11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना तथा 8.15 कि० मी० 11 KV over head line(with terminal equipments at consumer end and sending end, including security deposit) के संयोजन कार्यों हेतु क्रमशः रु० 48.10 लाख तथा रु० 52.00 लाख के औचित्यपूर्ण लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 में उपर्युक्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु क्रमशः रु० 48.10 लाख तथा रु० 52 लाख की धनराशि इस प्रकार कुल रु० 100,10,000.00(रुपये एक करोड़ दस हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक-1 के अनुसार संलग्नक-2 स्तम्भ-1 में उल्लिखित अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा इकाई प्रभारी(विद्युत), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, विद्युत इकाई श्रीनगर(गढ़वाल) व अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड टिहरी को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य में प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए उक्त को समयबद्ध ढंग से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

8- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10- जी०पी०डब्लू० फॉर्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने क कष्ट करें।

12- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 क अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर लिया जायेगा।

13- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्षक-4055 पुलिस प पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-00-211-पुलिस आवास, 04 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों क निर्माण, -00-24-गृह निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0-15 के कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-174(P)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/2010 दिनांक.13 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या-17.2 (1)/ XX-1-2010-24 निर्माण/2008-07तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
- 4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 5- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 6- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
- 7- पुलिस अधीक्षक, टिहरी।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 9- निजी सचिव, भा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 10- अपर सचिव, घोषणा अनुभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र संख्या: 1424/XXXV-4-203घो./2010 दिनांक 03.11.2010 घोषणा संख्या: 203/2010 के कम में।
- 11- अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।
- 12- परियोजना प्रबंधक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हरिद्वार।
- 13- इकाई प्रभारी(विद्युत), उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर, गढ़वाल।
- 14- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 15- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-5/नियोजन विभाग/गृह अनुभाग-04/एन0आई0सी0।
- 16- मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं०-१४२/XX-1-2010-24 निर्माण/2006-07, दिनांक: 18 जनवरी, 2011 का संलग्नक-1

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	जनपद	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	2010-11 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, नरेन्द्रगर में 11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना	टिहरी	उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम	52	52.00
2.	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, नरेन्द्रगर में 8.15 कि० मी० 11 KV over head line(with terminal equipments at consumer end and sending end, including security deposit)	टिहरी	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड टिहरी	48.10	48.10
			योग	100.10	100.10

(रुपये एक करोड़ दस हजार मात्र)

(जे० पी० जोशी)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या-1729 / XX-1-2010-24 निर्माण / 2006-07 दिनांक 18 जनवरी, 2011 का संलग्नक-2
अनुदान संख्या: 10, प्रशासनिक विभाग-गृह विभाग (वित्तीय वर्ष 2010-11)

बी.एम.-15 (प्रस्तर - 158)

नियंत्रक अधिकारी : पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। पुनर्विनियोजन का आवेदन पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधि क व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अध्यावधि में	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित धनराशि एवं लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत				4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत			क- स्तम्भ-1 उल्लिखित लेखाधन में प्रस्ताव प्राप्त न के कारण बचत उत्त है।
80-सामान्य,				211-पुलिस आवास			ख- स्तम्भ-1 उल्लिखित लेखाधन में प्राविधानित रु लाख की धनराशि सापेक्ष संपूर्ण धन अवमुक्त कर दिए के कारण कार्य रु0100.10 लाख पुनर्विनियोजन आवश्यकता है।
800-अन्य व्यय				03-पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
024- जेलों का आधुनिकीकरण							
24- बृहत निर्माण कार्य 50000	0	0	50000	24-बृहत निर्माण कार्य 10010(ख)	37510	39990	
योग 50000	0	0	50000	10010	37510	39990	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट में अनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता।

(जो भी जोश संयुक्त सचिव)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या- 174 (P) / वित्त अनु0-5 / 2010
देहरादून: दिनांक: 12 जनवरी, 2011

पुनर्विनियोजन स्वीकृत
(डॉ० एम० सी० जोशी)
अपर सचिव